



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 136 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2001/ज्येष्ठ 7, 1923

No. 136]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2001/JYAISTHA 7, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2001

अंतिम निष्कर्ष

विषय : यूरोपीय मंघ से एनिलिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—अंतिम निष्कर्ष।

सं. 21/1/2000-डी जी ए डी.—भारत सरकार वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 23 मई, 2001 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत तथा दिनांक 16 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- (ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

(iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भारत में यूरोपीय संघ के डेलिगेशन को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार भेजने की सलाह दी जाए ।

(iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 13.2.2001 को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया । इसके अलावा, अपने विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । पार्टियों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें तथा उनका खण्डन यदि कोई हो, प्रस्तुत करें ।

(v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्षों के अगोपनीय अंशोवाली फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवायी थी। उन सभी हितबद्ध पक्षों को सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी गयी थी ।

(vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परन्तु हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में विचार किया गया है ।

(vii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार का ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को खुलासा किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

(viii) इस मामले में जांच की अवधि 1.4.99 से 31.12.99 तक की है।

(ix) इस अधिसूचना में \*\*\* से गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना प्रदर्शित होती है तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही समझा गया है।

(x) शामिल देश यूरोपीय संघ (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) है और वर्तमान जांच में जांच की अवधि 15 अप्रैल, 1999 से 31 दिसम्बर, 99 तक की है।

**ख. विभिन्न हितबद्ध पक्षों के विचार:**

**2.0 याचिकाकर्त्ताओं के विचार:**

2.1 उन्होंने इस बात पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है कि निर्यातकों नामतः मै0 बी ए एस एफ, जर्मनी तथा बेयर ए जी, जर्मनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को एनिलिन का निर्यात करने का दावा किया है, इसलिए इन कंपनियों पर नयी शिपर समीक्षा संबंधी शर्त लागू होती है जैसा कि पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

2.2 क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में याचिकाकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि अमरीका और जापान के विरुद्ध पाटनरोधी जांच के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति एवं घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभावों को अमरीका तथा जापान में पाटन के साथ देखे जोन की आवश्यकता है।

2.3 जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से हुए आयात की मात्रा में वृद्धि हुयी है। हालांकि एनिलिन की मांग में वृद्धि हुयी थी, तथापि आयातों में अत्यधिक ऊँची दरों पर वृद्धि हुयी थी जिससे भारत में एनिलिन की मांग में यूरोपीय संघ से हुए आयातों के हिस्से में वृद्धि हुयी।

2.4 घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि हुयी है। तथापि, पाटित आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

2.5 कच्ची सामग्री बेन्जीन एनिलिन की उत्पादन लागत की मुख्य घटक है। हालांकि, कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुयी है तथापि, उद्योग उचित कीमत वृद्धि नहीं कर सका। आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम ४% जिसके परिणामस्वरूप कीमत में भारी कटौती हुयी।

2.6 आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य उत्पादन लागत से काफी कम था।

2.7 जहां शुल्क लगाने का संबंध है उन्होंने अनुरोध किया है कि शुल्क की प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार अमरीकी डालर के रूप में ही सिफारिश की जा ए।

#### याचिकाकर्त्ताओं के विचार:

##### डाईस्टफ मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया : के अनुरोधों के संबंध में

2.8 याचिकाकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि पाटन का मुद्दा किसी आयातक के लिए खुला नहीं है। यह मामला, ज्यादा से ज्यादा, केवल कि सी निर्यातिक द्वारा उठाया जा सकता है। वास्तव में सीगैट द्वारा किसी आयातक को पाटन मार्जिन वंड मुद्दे पर बहस करने से रोका भी गया है। जहाँ तक निर्यातकों का संबंध है इस संबंध में निर्यातकों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी है जिससे इस बात का स्वतः पता चलता है कि पाटन हुआ है।

जहाँ तक पहुँच मूल्य की गणना का संबंध है याचिकाकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि पहुँच मूल्य का आकलन करते समय एसोसिएशन : १ पहुँच मूल्य का आकलन करने के लिए एस ए डी ४% और पत्तन प्रभारों पर विचार किया है। जबकि पहुँच मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक जांच में निमानुसार उल्लेख किया गया है:

‘इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 तथा 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।

एस ए डी, जिसे पहुँच मूल्य का आकलन करने के लिए एसोसिएशन द्वारा जोड़ा गया है, को पहुँच मूल्य का आकलन करने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ बिक्री कर को भी शामिल नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, सीगैट ने पहले ही यह निर्णय दिया है कि पहुँच मूल्य की गणना करने के लिए पत्तन खर्चों को नहीं जोड़ा जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ से एनीलिन का कोई पाटन नहीं हुआ है । एसोसिएशन ने 650 अमरीकी डालर प्रति भी.टन की वर्तमान निर्यात कीमत का आरोप लगाया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि जांचोत्तर निर्यात कीमत जांच अवधि में हुए पाटन का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक है ।

एसोसिएशन ने उल्लेख किया है कि भारतीय उद्योग ने हाल ही में अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि की है ।

पहले दायर की गयी सूचना से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग उक्त सामग्री को उत्पादन लागत से काफी कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हुआ था । उद्योग से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उत्पादन लागत से काफी कम कीमतों पर उक्त सामग्री की बिक्री जारी रखेगा, क्योंकि उससे उद्योग अव्यावहारिक हो जाएगा और अन्ततोगत्वा वह रुग्ण बन जाएगा । जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकेगा:-

वर्ष	हानि
1996-97	100
1997-98	127
1998-99	221
जांच अवधि	620

1996-97 पर आधारित सूचकांक के आंकड़े 100 लिए गए हैं।

याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करना है और खुली तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया है:-

"पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रुकेगा।"

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह माना गया है कि प्रस्तावित उपाय के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और वस्तुतः यह पाटनरोधी शुल्क की मांग करने के प्रमुख कारणों में से एक है क्योंकि घरेलू उद्योग को अपनी उचित बिक्री कीमत प्राप्त करने से रोका गया था। इस बात का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि जांच अवधि के बाद मूल निविष्टि की लागत में भारी वृद्धि हुयी है।

जहाँ तक पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने का संबंध है, विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने उल्लेख किया है कि यह जांच एक व्यापार पत्रिका में निहित सूचना के आधार पर शुरू की गयी है जो कि सही नहीं है।

याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटन का प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपेक्षित होता है। याचिका में घरेलू उद्योग ने एक व्यापार

पत्रिका द्वारा उपलब्ध की गयी सूचना के आधार पर पाटन की पुष्टि की गयी है जो कि प्रथम दृष्टया पाटन की पुष्टि हेतु पर्याप्त आधार था । जांच शुरूआत संबंधी कारवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के निर्यातकों को उत्तर देने और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया है । यूरोपीय संघ के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । इस प्रकार का मामला होने के नाते, आयातकों अथवा उनकी एसोसिएशन द्वारा अब पाटन मार्जिन का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता ।

उन्होंने यह बात दोहरायी है कि सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के मुद्दे पर किसी आयातक अथवा उपयोक्ता एसोसिएशन द्वारा बहस नहीं की जा सकती क्योंकि वे संगत सूचना के लिए प्रियी नहीं हैं ।

जहाँ तक मांग को पूरा करेन के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थकता के बारे में दिए गए तर्कों का संबंध है याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उक्त एसोसिएशन का विवरण तथ्यता गलत है जैसा कि नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट होता है । भारत में एनिलिन की मांग और घरेलू उद्योग के पास क्षमता निम्नानुसार थीं -

विवरण	1997-98	1998-99	जांच की अवधि	1999-00 *
संबद्ध देशों से आयात	251	172	2652	3536
जापान/यू.एस.ए से आयात	5298	5065	0	0
अन्य देशों से आयात	259	41	43	57
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	38373	35820	31468	41957
मांग	44181	41098	34163	45550
रक्षापित क्षमता	48500	54100	40575	54100

\* वार्षिक

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग के पास मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इस प्रकार का मामला होने के कारण यह समझा में नहीं आता है कि हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क कैसे दिया है कि घरेलू उद्योग भारत में एनिलिन की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं है।

उन्होंने अनुरोध किया है कि राहत की मांग करने से पूर्व उद्योग के लिए देश में उक्त उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए समर्थ होना अपेक्षित नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे अनेक उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया है जिन मामलों में उत्पाद की मांग देश में उपलब्ध क्षमताओं से काफी अधिक रही है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होते हैं। ऐसे मामले में उपयोक्ता अपनी पुसंद के अनुसार अपनी सामग्री प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि कीमत कटौती का सिद्धांत झूठा और असत्य है, याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि यह तर्क वस्तुतः सही नहीं है और इसकी अनदेखी की जाए। प्रस्तुत आंकड़ों से इस बात का स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि जांच अवधि में कीमत में भारी कटौती हुयी है।

जहाँ तक एसोसिएशन के इस तर्क का संबंध है कि अगस्त - दिसम्बर, 1999 में एनिलिन का कोई आयात नहीं हुआ था और इसलिए उक्त अवधि में कोई क्षति नहीं हुयी थी, याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को समूची जांच अवधि में देखना होगा और न कि किसी एक माह अथवा एक दिन में। उन्होंने बताया है कि आयातों और क्षति संबंधी अन्य मापदंडों को समूची जांच अवधि में देखना अपेक्षित होता है। घरेलू उद्योग पर किसी बड़ी आयात खेप का प्रभाव अधिक लंबे समय तक महसूस किया जाता है।

एसोसिएशन ने यह बताया है कि याचिकाकर्ताओं का पाटन का आरोप केवल जर्मनी के खिलाफ है और इसलिए शुल्क केवल जर्मनी के खिलाफ लगाया जाना चाहिए और न कि यूरोपीय संघ के खिलाफ ।

यूरोपीय संघ में एनीलिन के अनेक उत्पादक हैं । यूरोपीय संघ में सीमाशुल्क संबंधी कोई सीमा नहीं है और यूरोपीय संघ में प्रचलित कीमतें उसी दायरे में हैं । यूरोपीय संघ से एनीलिन के आयातों के खिलाफ समग्र रूप से शुल्क लगाए बिना पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना कारगर सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अन्य उत्पादक (पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद) उन कीमतों पर एनीलिन का पाटन शुरू कर सकते हैं जिन पर जांच अवधि में इसका निर्यात किया गया था जिसकी परिणति भारतीय बाजार में सतत पाटन में हुई थी । यहां तक कि निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क की धोखाधड़ी करना भी कठिन नहीं होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह यूरोपीय संघ से हुए आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जैसा कि अनेक दूसरे मामलों में किया गया है ।

इसके अलावा जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में भी उल्लेख किया गया है, जिन निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर दिया है उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि इन उत्पादकों ने जांच अवधि में भारत को एनीलिन का निर्यात नहीं किया है । स्पष्टतः यूरोपीय संघ में ऐसे अन्य निर्यातक हैं जिन्होंने भारत को एनीलिन का निर्यात किया है । इस प्रकार समग्र यूरोपीय संघ के खिलाफ शुल्क लगाए बिना पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना कारगर सिद्ध नहीं हो सकता । याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से समग्र यूरोपीय संघ के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ।

एसोसिएशन द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि एनिलिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसकी उत्पादन लागत में वृद्धि होगी जिससे चीन से रंजक पदार्थों के आयातों में वृद्धि हो सकती है।

याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है निर्दिष्ट प्राधिकारी का सिद्धान्त और व्यवहार दोनों हितबद्ध पार्टियों को बचाना है। यदि संबद्ध उद्योग को क्षति का कोई खतरा होता है तो यूरोपीय संघ के उत्पादकों तथा अन्य निर्यातकों द्वारा किए गए पाटन के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क की पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा किसी अन्य उचित प्राधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं और न कि एनिलिन उद्योग के सामने बाधा खड़ी करने के लिए।

#### 2.9 जीडीएमए द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के बारे में

जहां तक मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की अपर्याप्त क्षमता का संबंध है, याचिकाकर्त्ताओं ने यह अभ्यावेदन दिया है कि मांग की कमी के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग घटी हुई क्षमता पर अपना संयंत्र चलाने के लिए बाध्य हुआ है और उसके पास पर्याप्त वर्तु सूचियां हैं। उन्होंने यह बात दोहराई है कि मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग का असमर्थ होना पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने का कोई कारण नहीं बनता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से केवल कीमतें उचित स्तर पर आ जाएंगी और उससे देश में होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे। इस प्रकार इस वजह से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

जहां तक जीडीएमए द्वारा दिए गए इन तर्कों का संबंध है कि विभिन्न उत्पादों के निर्यात के कारण एनिलिन का आयात आवश्यक है, याचिकाकर्त्ताओं ने दोहराया है कि पाटनरोधी शुल्क निर्यात उत्पादन हेतु आयातों के खिलाफ संदेय नहीं होता है ।

जहां तक एनिलिन की निर्यात कीमत के बारे में 650 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन का संकेत दिए जाने का संबंध है, यह दोहराया जाता है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के मुद्दे को तय करने के लिए मौजूदा निर्यात कीमत प्रासंगिक नहीं है ।

जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच अवधि के दौरान यूरोप में कीमतें लगभग 650-655 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन की थी, भारत को निर्यात की कीमत इसी अवधि के दौरान औसतन 413 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन (सीआइएफ) की थी । समुद्री भाड़े और अन्य खर्चों पर विचार करते हुए निर्यातकों को कारखानागत प्राप्ति जीडीएमए द्वारा उद्धृत 650 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन की कीमत से काफी कम थी । इससे पाटन सिद्ध होता है ।

याचिकाकर्त्ताओं ने अनेक मामलों में दर गए सी गेट के निर्णय का भी उल्लेख किया है कि पाटन और पाटन मार्जन का मुद्दा किसी निर्यातक के लिए बहस हेतु खुला नहीं होता है । आयातक (उपयोक्ता एसोसिएशन) पाटन और पाटन मार्जन के निर्धारण हेतु अपेक्षित वास्तविक सूचना के लिए कोई प्रिवी नहीं है अतः इस वजह से उक्त तर्क को अस्वीकृत करना अपेक्षित है ।

याचिकाकर्त्ताओं ने बताया है कि जहां तक उपयोक्ता उद्योग के इस दावे का संबंध है कि उत्पाद की परिवर्तन लागत के रूप में ड्यूपोंट ने 150 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन का अनुरोध किया है, इस दावे का कोई आधार नहीं है और न तो आयातक और न ही उपयोक्ता एसोसिएशन ऐसे आंकड़ों के लिए प्रिवी है ।

जहां तक जांच अवधि के बाद एनिलिन की कीमतों में हुई वृद्धि का संबंध है, जांच में पाटन अथवा क्षति के मुद्दे को उठाना प्रासंगिक नहीं है।

उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सामग्री की आपूर्ति करने के विकल्प पर निर्यातक की सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी के कहने पर मै0 एनसीपीएल द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए मुम्बई में 21.3.2001 को जीडीएमए तथा डाइस्टफ मैनुफेक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा बुलाई गई बैठक के संदर्भ में उपयोक्ताओं ने ऐसे किसी बैठक में कोई रुचि नहीं दिखाई है, याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का एकमात्र उद्देश्य निर्यातकों द्वारा पाटन से प्राप्त अनुचित लाभों तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त अल्पकालिक लाभों को समाप्त करना है।

जहां तक मै0 बीएसएफ का संबंध है, इस कंपनी ने जांच अवधि के दौरान किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है। किसी निर्यात के बिना प्राधिकारी द्वारा अलग से कोई निर्धारण नहीं किया जा सका। जिन कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है उनके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नए शिपर समीक्षा हेतु आवेदन रना अपेक्षित होता है।

इसके अलावा जहां तक बीएसएफ द्वारा दाया उत्तर के आधार पर यूरोपीय संघ में सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि बीएसएफ ने जांच अवधि के दौरान भारत को किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है। जिस निर्यातक ने जांच अवधि में निर्यात किया है उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। निर्यातक द्वारा दायर उत्तर के आधार पर असहयोगी नियंतकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का तात्पर्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन्हें असहयोग हेतु पुरस्कृत करना होगा। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि असहयोगी

निर्यातिकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण ऐसे निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए जिसमें जांच अवधि के दौरान भारत को किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है और जो भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत ' ऋ शिपर समीक्षा का हकदार है ।

#### ग. निर्यातिकों और आयातकों के विचार

##### निर्यातिकों के विचार

###### 2.10 मै0 बीएसएफ जर्मनी

जर्मनी में एनिलिन के उत्पादकों ने बताया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान एनिलिन का निर्यात नहीं किया है । तथापि, उन्होंने घरेलू बाजार में दुई विक्रियों के बारे में कुछ सूचना प्रस्तुत की है । मै0 बीएसएफ ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हो ।

##### आयातकों के विचार

###### 2.11 मै0 नेशनल आर्गेनिक्स कॉमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि�0 (एनओसीआईएल)

उन्होंने उल्लेख किया है कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मै0 बीएसएफ ने बताया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित सामान्य मूल्य छोटी मात्रा में ड्रम लाटों के लिए वसूली गई कीमतें हो सकती हैं और बड़ी बल्क खेपों के लिए नियमित कीमतें कम होनी चाहिए ।

मै0 बीएसएफ ने जांच अवधि के दौरान किसी उत्पादन का निर्यात न किए जाने के बावजूद भी सामान्य मूल्य के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की पेशकश की थी ।

उन्होंने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि नवम्बर में ई यू के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कीमतों में 1500 रुपए प्रति टन

की मामूली धनराशि की वृद्धि हुई है क्योंकि विगत में कीमतों में बढ़ोत्तरी नियमित और सतत आधार पर हुई है।

मात्रा, कीमत प्राप्ति और लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अलावा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

जहां तक एनिलिन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कीमत व्यवन्बद्धता का संबंध है मै0 एनसीपीएल ने लागत जमा कीमत प्रबंध को तरजीह दी और दोनों हितबद्ध पार्टियों को पारस्परिक रूप में स्वीकार्य व्यवस्था करने और उस पर विचार विमर्श हेतु पर्याप्त समय दिया जाए।

जहां तक आयता संबंधी आंकड़ों का संबंध है उन्होंने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कांडला पत्तन से उनके द्वारा एकत्र की गई सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते।

उन्होंने उल्लेख किया है कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित जर्मनी के एनिलिन के दो विनिर्माता भारत को एनिलिन का निर्यात कर रहे हैं, यह सिद्ध नहीं होता है कि उससे याचिकाकर्ताओं को वास्तविक क्षति हुई है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ है।

## 2.12 मै0 क्लर कैम लिमिटेड (क्लैरिएंट) थाणे

आयातकों ने बताया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से रबड़ रसायन, पिगमेंट और रंजक पदार्थ विनिर्माता एककों पर बुरा असर पड़ा है।

जो लघु उत्पादक आयातित एनिलिन, यदि उसे बैरलों में आयात किया गया है, की तुलना में स्वदेशी विनिर्माताओं से बैरलों में बंद कच्ची सामग्री की खरीद को तरजीह देते हैं, उनके लिए अतिरिक्त आयात अव्यवहारिक हो गए हैं।

एनिलिन पर लगाए गए शुल्क से विनिर्माता एककों के हितों को नुकसान हो रहा है क्योंकि संबद्ध एककों को निविष्टियों अर्थात् एनिलिन की उच्च लागत के कारण अपने अंतिम उत्पादों के उत्पादन में कमी लानी होगी ।

### **2.13 दि डाइस्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया मुम्बई:**

उन्होंने उल्लेख किया है कि यूरोपीय संघ के विनिर्माताओं/व्यापारियों द्वारा एनिलिन का कोई पाटन नहीं किया गया । इसके आपूर्तिकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि आयातित एनिलिन की पहुंच लागत घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई कीमत से अधिक है ।

उन्होंने उल्लेख किया है कि घरेलू विनिर्माताओं ने एनिलिन की अपनी कीमतों में लगातार वृद्धि की है जिससे एनिलिन के उपभोक्ताओं के विभिन्न संबद्ध उत्पादों की लागत प्रभावित हुई है ।

व्यापार पत्रिका पर आधारित कीमत संबंधी सूचना विश्वसनीय नहीं है और उसे गोपनीय सूचना नहीं माना जा सकता ।

घरेलू विनिर्माता की कुल क्षमता देश में मांग से कम है । इस प्रकार देश में एनिलिन का आयात करने की बाध्यता है ।

चूंकि पाटन का आरोप जर्मनी के केवल दो विनिर्माताओं से संबंधित है इसलिए याचिकाकर्ता केवल जर्मनी मूल के एनिलिन पर शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं न कि यूरोपीय संघ की किसी भी जगह तभी एनिलेन पर ।

आयातकों ने बताया है कि उन तीनों उत्पादों, नामतः एनिलिन, सोडियम नाइट्राइट और कास्टिक सोडा, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, की स्थानीय कीमतों में संयोगवश पर्याप्त वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग द्वारा उपभोक्ता उद्योगों की लागत पर अपनी कीमतों को बढ़ाया जा रहा है ।

**2.14 मैसर्स गुजरात डाइस्ट्रफ मैन्युफैक्चरर्स  
एसोसिएशन (जीडीएमए), अहमदाबाद**

मैसर्स जीडीएमए ने वर्तमान पाटनरोधी जांच में अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की स्वीकृति देने का अनुरोध किया था । बैठक 20.3.2001 को हुई थी । उन्होंने बताया है कि उन्होंने दिनांक 21.11.2000 की राजपत्र अधिसूचना के आधार पर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए थे । तथापि, उन्हें इस संबंध में घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत पुनरुत्तर की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई थी । मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु एनिलिन का आयात करना अनिवार्य है ।

मैसर्स जीडीएमए ने भी अन्य आयातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समान ही मुद्दों को उठाया है ।

**2.15 मैसर्स मरदिया कॉमिकल्स लि., अहमदाबाद**

उन्होंने बताया है कि अगस्त, 2000 से अप्रैल, 2001 के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा घरेलू बाजार में एनिलिन की कीमतों में वृद्धि की गई है ।

### **2.16 मैसर्स गणेश कैमिकल्स, मुम्बई**

उन्होंने बाया है कि एनिलिन के घरेलू विनिर्माता उनके सामने आई घरेलू एवं अन्य समस्याओं के कारण एनिलिन उत्पादन का उत्पादन और उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे । एनिलिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम रही हैं क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमतों में भी कमी आई थी ।

### **3.0 प्राधिकारी द्वारा जांच**

3.1 जहां तक जापान और यूएसए के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने का संबंध है, यह एनिलिन की घरेलू कीमत के सुधार में स्वाभाविक रूप से लाभकारी होगा ।

3.2 जहां तक जापान/यूएसए से आयात की मात्रा के यूरोप से जोड़ने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई मात्राओं की तुलना में जापान/यूएसए से आयात की मात्रा शून्य थी ।

3.3 जहां तक अन्य हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त जवाब के अगोपनीय अंश की प्रति का संबंध है, इसे किसी अन्य हितबद्ध पार्टी द्वारा निरीक्षण करने हेतु सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।

3.4 जहां तक जीडीएमए से अभ्यावेदन दिए जाने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने प्रारंभिक निष्कर्षों से पहले जाच पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी और न ही उन्होंने 13.2.2001 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था । तथापि, सुनवाई की स्वीकृति हेतु अनुरोध के अभ्यावेदन पर प्राधिकारी ने उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी और जिस पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया गया है ।

3.5 जहां तक कुछ हितबद्ध पार्टियों के इन तर्कों का संबंध है कि विभिन्न आकड़ों का वार्षिक स्वरूप गलत है, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जांच में जांच अवधि नौ महीने की है । जांच अवधि में हुई आयातों की तुलना पिछली अवधि के साथ करने के उद्देश्य से, ये आकड़े या तो

मासिक आधार पर हो सकते हैं या वार्षिक आधार पर । एक रूपता के प्रयोजनार्थ पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना जांच अवधि के लिए वार्षिक आंकड़ों के साथ की गई है । इसके अलवा, जहां तक अनुपात के मुद्दे का संबंध है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अनुपात अपरिवर्तित रहता है चाहे वार्षिक आंकड़ा लिया गया हो अथवा वास्तविक आंकड़ा लिया गया हो ।

3.6 एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि एनिलिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध उत्पाद उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे भारतीय बाजार में एनिलिन की कीमतों में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप डाईस्टफ उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी ।

3.7 हांलाकि विवादित मुद्दा यह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में एनिलिन की कीमतों में वृद्धि होगी, तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक हित का मुद्दा वर्तमान जांच के दायरे से बाहर है और नियमों के तहत इसकी व्यवस्था नहीं है । इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सार्वजनिक हित के मुद्दे की जांच करना अपेक्षित नहीं है । प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा-ट "भारतीय उद्योग हित एवं अन्य मुद्दों" की पुष्टि करते हैं ।

3.8 जहां तक मैसर्स बीएएसएफ का संबंध है, कम्पनी ने जांच अवधि के दौरान किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है । किसी निर्यात के बिना प्राधिकारी द्वारा अलग से कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता । जिन कम्पनियों में जांच अवधि में किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया है उनके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष "नए शिपर समीक्षा" के लिए आवेदन दायर करना अपेक्षित होता है ।

3.9 जहां तक मैसर्स बीएएसएफ द्वारा सामान्य मूल्य के बारे में सूचना प्रस्तुत करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब उक्त कम्पनी ने विचाराधीन वस्तु का निर्यात नहीं किया है तब सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता और प्रस्तुत की गई सूचना उन अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु संगत नहीं है, जिन्होंने पाटनरोधी जांच में सहयोग नहीं किया है । इन परिस्थितियों में मैसर्स बीएएसएफ द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार नहीं किया गया है ।

### इस संबंध में भारतीय पाटनरोधी नियमों में निम्नानुसार उल्लेख है

ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनके बारे में मूलतः जांच नहीं की गई है ।

(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संदर्भाधीन निर्यातक देश के ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेगा, जिन्होने जांच अवधि के दौरान भारत को उक्त उत्पाद का निर्यात नहीं किया है बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करते हों कि वे उस निर्यातक देश के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जिन्हें उक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों के अधीन रखा गया है ।

3.10 नियमों के अनुसार, पाटन मार्जिनों का निर्धारण निर्यातक विशिष्ट होता है । चूंकि मैसर्स बीएएसएफ ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है इसलिए, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर उनके लिए अलग से पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

3.11 उपरोक्त परिस्थितियों में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम्पनी के लिए वर्तमान जांच पूरी होने के बाद "नए शिपर समीक्षा" हेतु आवेदन दायर करना अपेक्षित है ।

### (घ) उठाए गए मुद्दों की जांच

4. याचिकाकर्ता, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की गई है, जहां तक वे नियमों के अनुसार संगत हैं और इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, और उन पर विचार किया गया है तथा इन निष्कर्षों में उचित जगहों पर उन पर कार्रवाई की गयी हैं ।

**(ड.) जांच के अधीन उत्पाद**

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एनिलिन तेल के नाम से भी जाना जाता है। एनिलिन पारदर्शी, तेल है। जब इसका आसवन किया जाता है तो यह रंगहीन से पीला हो जाता है। प्रकाश या हवा में लाने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन एक प्राथमिक ऐमीन योगिक है और यह औषध, भेषज, रंग और रंजक मध्यवर्ती जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक मूल काबिनिक रसायन है। एनिलिन का प्रयोग रबड़ रसायन, विस्फोटक, रेजिन इत्यादि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी किया जाता है।

एनिलिन रबड़ रसायन (वलकेनाइजेशन, एसलेरेटर, एंटीआक्साइडेंट) रंग, एनालजिन जैसी औषध, सत्पा औषध, फोटोग्राफिक रसायन, (हाइड्रोक्यूनोन), आइसोसाइनेट्स (एमडीआई या मैथलिन डाइफैनिलिन डाई आईसोसाइनेट) के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है। भारत में एनिलिन के उत्पादन के 70% के भाग का इस्तेमाल रबड़ रसायन, औषध और औषध मध्यवर्ती तथा रंग उद्योगों में किया जाता है जबकि एनिलिन के उत्पादन के 80% भाग का इस्तेमाल विश्वभर में एमडीआई में किया जाता है।

एनिलिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29, सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

**च. समान वस्तु**

6.1 समान वस्तु की परिभाषा में निम्नानुसार उल्लेख है:-

“ समान वस्तु का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जाने वाली जांचाधीन वस्तु के समरूप या सभी प्रकार से समान हो अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में किसी दूसरी वस्तु से है जो यद्यपि सभी प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से काफी मिलती जुलती हैं। ”

6.2 एनिलिन का उत्पादन और बिक्री आईएसआई मानकों के अनुसार विनिर्देशनों में की जाती है जिससे रसायन के गुण-धर्मों का पता चलता है। एनिलिन की गुणवत्ता का वर्णन उसकी शुद्धता के रूप में किया जाता है। एनिलिन की मानक गुणवत्ता में भार के रूप में 99.8% की शुद्धता निहित होती है। तथापि, एनिलिन के उत्पादन हेतु प्रक्रिया, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है।

6.3 प्राधिकारी ने यह पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एनिलिन और यूरोपीय संघ से आयातित संबद्ध उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों इत्यादि जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

6.4 उपरोक्त के महेनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एनिलिन यूरोपीय संघ से आयातित एनिलिन के समान वस्तु है।

#### (छ) घरेलू उद्योग

7.0 यह याचिका मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिंग (एचओसीएल), मैसर्स नर्मदा कैमेटूर पैट्रो कैमिकल्स लिंग (एचसीपीएल) और मैसर्स एनीरोक्स पिगमैट्स लिंग द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। ये तीनों इकाइयां भारत में एनिलिन की एक मात्र उत्पादक हैं। अतः याचिकाकर्ता कम्पनियों का हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन बनता है और उनके पास नियमों के तहत याचिका दायर करने का अपेक्षित आधार है।

7.1 पूर्वोक्त के महेनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिकाकर्ता के पास नियमों के तहत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है।

#### ज. पाटन

8.0 धारा 9क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

(i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या

(ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक विक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसक सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

### निर्यातकों के दावे

**8.1 मै0 बीएएसएफः-** उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान एनीलिन का निर्यात नहीं किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य उनके घरेलू बाजार में प्रस्तुत की गई उनकी सूचना पर आधारित होना चाहिए और यह संकेत दिया है कि वे निकट भविष्य में भारत को एनीलिन का निर्यात करने के इच्छुक हैं।

**8.2 मै0 बेयरः-** उन्होंने यह कहा है कि बेयर एजी ने दिनांक 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक की जांच अवधि में भारत को एनीलिन का निर्यात नहीं किया है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

8.3 प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों निर्यातकों, नामतः मै0 बीएएसएफ, जर्मनी तथा मै0 बेयर्स एजी, जर्मनी ने यह कहा है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान एनीलिन का निर्यात नहीं किया है और वे नए शिपर के रूप में पृथक निर्धारण के लिए अनुरोध कर सकते हैं - उपरोक्त नियम-22 ।

8.4 जहां तक सामान्य मूल्य के संबंध में मै0 बीएएसएफ द्वारा सूचना प्रस्तुत करने तथा कुछ हितबद्ध पार्टियों के इस दावे का संबंध है कि जर्मनी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी आधार पर होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है । कम्पनी ने जांच अवधि के लिए कारखाना लागत एवं घरेलू बिक्री से प्राप्त लाभ तथा भारत को छोड़कर अन्य देशों को किए गए निर्यात का बौरा प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपनी लेखा-परीक्षा एवं लेखाओं से संबंधित ऐसा कोई ब्यौरा/कार्यशील गणना प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि उत्पाद की बिक्री उत्पादन लागत से अधिक कीमत पर की गई थी । इससे यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री अपने घरेलू बाजार में अथवा भारत को छोड़कर अन्य देशों में की है । वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट समेकित लगती है । विचाराधीन उत्पाद के बारे में बहुत कम उल्लेख किया गया है । कम्पनी ने अपनी घरेलू बिक्री के संबंध में चुनिन्दा बीजकों को जर्मन भाषा में इसके अंग्रेजी रूपान्तर के बिना प्रस्तुत किया है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जब कम्पनी ने विचाराधीन वस्तु का निर्यात ही नहीं किया है तब सामान्य मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत की गई सूचना ऐसे अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए संगत नहीं है जिन्होंने पाटनरोधी जांच में सहयोग नहीं दिया है । इन परिस्थितियों में सामान्य मूल्य के संबंध में मै0 बीएएसएफ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार नहीं किया गया है ।

8.5 ईयू के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रश्नावली की सूचना प्रस्तुत भ किए जाने के मद्देनजर, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के बारे में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर

विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ा जैसाकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी थी और जो सर्वोत्तम सूचना उनके पास उपलब्ध थी ।

### सामान्य मूल्य

8.6 याचिकाकर्ताओं ने यूरोप में उक्त वस्तु की कीमत के संबंध में 'कैमिकल वीक यूके' नामक पत्रिका के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें यूरोपीय बाजारों में एनिलिन की सीआईएफ कीमतें 880-925 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के बीच होने की सूचना दी गयी है । प्राधिकारी यूरोपीय संघ में कारखाना द्वार स्तर पर तथा रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में किए गए दावे पर विश्वास करते हैं । सामान्य मूल्य का निर्धारण \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मी. टन किया गया है ।

### निर्यात कीमत

8.7 याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की अवधि के लिए निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जैसाकि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता) द्वारा सूचित किया गया है । ईयू से हुए आयातों की मात्रा 1251.7 मी० टन होने की सूचना दी गई है और कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन, पत्तन हैण्डलिंग के कारण समायोजनों का दावा किया गया है ।

8.8 सीमाशुल्क दैनिक सूची, कांडला पत्तन द्वारा यथा सूचित आयात के आंकड़े से जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से हुए आयात की 2652 मी. टन की मात्रा का संकेत मिलता है जो डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा सूचित मात्रा से काफी अधिक है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए सीमाशुल्क दैनिक सूची द्वारा यथा सूचित आयात के आंकड़े पर विश्वास किया है । प्राधिकारी ने समुद्री भाड़ा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन, पत्तन हैण्डलिंग प्रभारों के कारण समायोजनों की अनुमति दी है और तदनुसार निर्यात कीमत (कारखाना द्वार पर) का निर्धारण \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मी. टन किया गया है ।

### पाटन मार्जिन

8.9 सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है:-

‘पाटन का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के एक समान स्तर पर, सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभाव उसी समायावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी। उक्त अंतर में बिक्री की शर्त, कराधान, व्यापार के स्तर मात्राएँ, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर शामिल हैं, जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।’

8.10 सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य प्रकाशित सूचना को हिसाब में लिया। जैसाकि उपर बौरा दिया गया है, सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण कारखाना द्वार पर किया गया है। सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना से \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मी. टन के पाटन मार्जिन का पता चलता है। ईयू के लिए निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित पाटन मार्जिन 166.17% बैठता है।

### अ. क्षति

9.0 उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में ‘.....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा।’ कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस

प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो कि अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

नियमावली के अनुबंध-॥ के नियम (III) के अनुसार यह अपेक्षित है कि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के मामले में जब पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों का संचयी रूप से आकलन करेगा । तथापि, इस प्रकार का आकलन तभी किया जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि:-

(क) प्रत्येक देश से अयातों के संबंध में प्रमाणित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देशों को निर्यात 3% से कम है वहां इन आयातों का हिस्सा संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के 7% से अधिक बनता हो; और

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से उचित है ।

9.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन तथा संबद्ध देश से हुए आयातों की मात्रा ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है । आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन भी समुचित है क्योंकि संबद्ध देशों की निर्यात कीमतें भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रही थी ।

9.2 भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध-॥ (iv) के अनुसार ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे:- आयात की मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि ।

98 आयातों की मात्रा:-

डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा यथा सूचित आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:-

	1997-98	1998-99	जांच (अप्रैल-दिस.99)	वार्षिक
ईयू से आयात (मी.टन)	251	172	*2652	(3536)
कुल आयात में ईयू का हिस्सा %	4.3	3.3	98.4	
जापान/यूएसए से आयात (मी.टन)	5298	5065	0	(0)
अन्य देशों से आयात (मी. टन)	298	40	43	(57)
कुल आयात (मी. टन)	5847	5277	2695	
भारतीय उत्पादकों की बिक्री(मी. टन)	38373	35820	31468	(41957)
देश में कुल मांग (मी. टन)	44220	41097	34163	(45550)
मांग में बाजार हिस्सा				
ईयू	0.6	0.5	7.8	
जापान/यूएसए	11.9	12.3	0	
अन्य	0.7	0.1	0.1	
घरेलू उद्योग	86.8	87.1	92.1	
	100.0	100.0	100.0	

स्रोत: सीमाशुल्क दैनिक सूची-काउला पत्रन

जैसाकि उपरोक्त से देखा सकता है कि ईयू से होने वाले आयातों की मात्रा, जो वर्ष 1997-98 के दौरान 251 मी. टन थी, वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 2652 मी. टन (3536 मी. टन वार्षिक) हो गई। कुल आयातों में यूरोपीय संघ का हिस्सा 1997-98 में 4.3% से बढ़कर जांच अवधि में 98.4% हो गया। जापान, यूएसए से होने वाले आयातों की मात्रा, जो (1997-98 में) 5298 मी. टन थी, जांच अवधि के दौरान घटकर शून्य रह गई। यह नोट किया जा सकता है कि जापान/यूएसए से होने वाले कथित पाटन के लिए पाटनरोधी जांच की कार्रवाई ईयू के विरुद्ध वर्तमान जांच की शुरुआत से पहले चल रही थी।

हालाँकि यूरोपीय संघ के संबंध में मांग में बाजार हिस्से में 0.6% (97-98) से 7.8% (जांच अवधि) तक कई गुणा वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी 86.8% (97-98) से 92.1% (जांच अवधि) तक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

जैसाकि देखा गया है कि पिछले वर्षों में ज्ञापन/यूएसए के लिए मांग में ईयू द्वारा बड़े अनुपात में हिस्सेदारी की गई है तथा जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अल्प मात्रा में हिस्सेदारी की गई है।

#### 9.4 उत्पादन और क्षमता उपयोग

यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता कपंनियों (अर्थात् एचओसीएल, एनसीपीएल और एनीरोक्स पिगमैंट्स) की उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:-

वर्ष	क्षमता (मी. टन)	उत्पादन (मी.टन)	क्षमता उपयोग %
1996-97	48100	40435	84.06
1997-98	48500	47254	97.43
1998-99	49100	41780	85.09
जांच अवधि(अप्रै-दिस)	36825	32768	88.98
वार्षिक	49100	43689	88.98

घरेलू उद्योग का उत्पादन 1997-98 में हुए 47254 मी. टन से गिरकर जांच अवधि के दौरान 43689 मी. टन (वार्षिक) हो गया था। क्षमता उपयोग, जो 1997-98 के दौरान 97.43% था, जांच अवधि के दौरान गिरकर 88.98 हो गया।

#### 9.5 बिक्री मात्रा:-

पिछले तीन वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नानुसार रही थी:-

मी. टन में

1997-98	1998-99	जांच अवधि	वार्षिक
38373	35820	31468	41957

घरेलू उद्योग की बिक्री में 1998-99 में अत्यधिक कमी आई है। यद्यपि चालू वर्ष में बिक्री में सुधार हुआ है, तथापि यह एनीलिन प्रचालनों के संबंध में अलग-अलग इकाइयों द्वारा उठाई जा रही पर्याप्त हानि के कारण हुआ है।

9.6 आन्तिम स्टॉकः-

मी. टन

1997-98	1998-99	जांच अवधि	वार्षिक
2226	2252	2881	3841

यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का अन्तिम स्टॉक 1997-98 के दौरान 2226 मी. टन था जो जांच अवधि (अप्रैल-दिसेंबर 99) के दौरान बढ़कर 2881 मी. टन हो गया।

**9.7 कीमत में कटौतीः-** यूरोपीय संघ से हुए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। इस प्रकार घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत से काफी कम कीमत पर बिकी कर रहा है। इस प्रकार यूरोपीय संघ से हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमत में भारी कटौती करनी पड़ रही है।

9.8 घरेलू बिक्री

( / मे )

	1997-98	1998-99	जांच अवधि (अप्रैल से दिसम्बर/99)
एचओसीएल	100	93	88
एनसीपीएल	100	89	81
एनीरोक्स	100	94	87
घरेलू उद्योग के औरक्स	100	91	85

जैसाकि उपरोक्त से देखा जा सकता है 9% में घरेलू बिक्री कीमत में 1997-98 की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों से भारतीय उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई थी। इससे उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों को बढ़ाने से वंचित होना पड़ा।

### **9.9 क्षति संबंधी निष्कर्ष**

- जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है।
- सीआईएफ आयात कीमत में गिरावट आ रही है।
- वर्ष 97-98 की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट दिखाई दी है।
- यूरोपीय संघ से आयातित वस्तुओं का बाजार हिस्सा बढ़ गया है।
- जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में उत्पादन की लागत तो बढ़ गई है लेकिन जांच अवधि के दौरान कीमत प्राप्ति कम हो गई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान हानि हुई है।
- सम्बद्ध देशों से आयातों के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में कीमतों में गिरावट आई है।

9.10 उपर्युक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को यूरोपीय संघ के मूल के एनीलिन के आयातों से वास्तविक क्षति हुई है।

### **अ. कारणात्मक संबंध**

10.0 प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में एनीलिन की मांग में कोई भारी उतार-चढ़ाव नहीं रहा है। घरेलू उद्योग विश्व में एनीलिन के सबसे छोटे उत्पादकों में से एक है और भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में एनीलिन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 1998-99 में एनीलिन की वैश्विक कीमतों में भारी गिरावट आई थी और इसका उन कीमतों पर प्रभाव पड़ा था जिन कीमतों पर इसका भारत में आयात किया गया था। इससे घरेलू उत्पादकों के प्रचालनों और लाभ प्रदत्ता पर प्रभाव पड़ा क्योंकि जांच की अवधि के दौरान एनीलिन का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं द्वारा पाटन किया गया था।

10.1 यह प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से हुए आयातों से वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में कमी आई है। घरेलू उद्योग एनीलिन के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों/फीड स्टाक की कीमतों में वृद्धि के कारण आयातित

उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ बराबरी करने में विफल रहा है। 1996 से पैट्रोलियम, ईंधन तेल और बैन्जिन की कीमतों में वृद्धि होनी आरम्भ हुई। सम्बद्ध देशों से हुए आयातों से घरेलू उत्पाद की कीमतों में कटौती हुई जिससे घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री अलाभकरी कीमतों पर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को हानि हुई। इस प्रकार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबंधित देशों से पाटित आयातों के कारण हुई थी।

#### ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

11.0 सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः बहाल करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

11.1 यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्भीत उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब, जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक ही प्रतिबंधित कर दी जाए जो कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों के समाप्त किया जा सकेगा, भारतीय उद्योग के हास को रोका जा सकेगा और इस प्रकार एनिलिन के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होंगे। पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

11.2 घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षमता उपयोग के ईस्टतम स्तर पर उत्पादन की ईस्टतम लागत पर विचार करके भारत में घरेलू उद्योग के लिए एनिलिन की उचित बिक्री कीमत पर विश्वास किया है।

### निष्कर्ष

12.0 पूर्वोत्तर पर विचार करने के पश्चात यह देखा गया है कि

- यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एनिलिन का सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके कारण पाटन हुआ है;
- भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- उक्त क्षति सम्बद्ध देशों से हुए आयातों के कारण हुई है।

सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एनिलिन के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा गया है।

13.0 प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी, और ऐसे शुल्क को लगाने की तारीख पर विचार किया। (यथासंशोधित उपरोक्त नियम-4 की खण्ड (घ) )

14.0 पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था जिसे यदि लगाया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2921.41 के तहत आने वाले यूरोपीय संघ के मूल के या वहाँ से निर्यातित एनिलिन पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क की राशि कालम-3 में दी गई राशि होगी।

देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	शुल्क की राशि अमरीकी डा. प्र. कि.
1	2	3
यूरोपीय संघ	सभी निर्यातक	0.342

15.0 इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3.3क 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।

16.0 उपरोक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी दिनांक 14.8.2000 के प्रारंभिक निष्कर्षों और दिनांक 6.11.2000 के शुद्धि पत्र की पुष्टि करते हैं ।

17.0 इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समर्थ दायर की जा सकेगी ।

ए.ल. वी. मस्त्राणि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2001

#### Final Finding

**Subject :** Anti-Dumping Investigation concerning imports of Aniline from European Union—Final Findings.

**No. 21/1/2000-DGAD.—** The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

#### A PROCEDURE

The procedure described below has been followed with regard to the investigations:

- i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified Initiation of anti dumping investigation vide notification dated 29<sup>th</sup> May, 2000 and Preliminary Findings vide notification dated 16<sup>th</sup> November, 2000 and requested the interested parties to make their views known in writing within 40 days from the date of its publication.
- ii. The Authority forwarded a copy of Preliminary Findings to the known interested parties who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within 40 days of the date of the letter

- iii. The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Delegation of European Union in India with a request that exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings.
- iv. The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 13.2.2001. Further, all the parties presenting views orally were requested to file written submission of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.
- v. The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties. All interested parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;
- vi. Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties have been considered in the preliminary findings and/or these findings.
- vii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.
- viii. The period of investigations-(POI) covered is 1<sup>st</sup> April, 1999 to 31<sup>st</sup> December 1999 ;

- ix. \*\*\* in this notification represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the rules;
- x. The country involved in the present investigations is European Union (also herein after referred to as subject country) and the period of investigation for the present investigation is 1<sup>st</sup> April, 1999 to 31<sup>st</sup> December, 1999;

**B. VIEWS OF VARIOUS INTERESTED PARTIES:**

**2.0 Views of the Petitioners:**

- 2.1 They have drawn the attention of Designated Authority that the claims of exporters, namely, M/s. BASF, Germany and Bayer AG, Germany have not exported Aniline to India during the period of investigation hence these companies attract new shipper revenue condition, as laid down under Rule 22 of Anti-dumping Rules.
- 2.2 On injury and causal link, the petitioners have stated that anti-dumping investigations against USA and Japan resulted in imposition of anti-dumping duty. Injury to the domestic industry and the adverse affects of dumped imports on the domestic industry is, therefore, required to be seen alongwith dumping in USA and Japan.
- 2.3 Import volumes from European Union increased during period of investigation. Though demand for Aniline increased, imports increased at significantly higher rates, which resulted in increase in share of imports from European Union in the demand of Aniline in India.
- 2.4 Production and sales of domestic industry increased. However, the domestic industry was forced to reduce selling prices in view of the dumped imports.

2.5 Raw material Benzene forms a major cost of production of Aniline. While the prices of raw material increased the industry could not effect legitimate price increase. Landed value of imported material was below the selling price of the domestic industry resulting in severe price undercutting.

2.6 Landed value of imported material was significantly below the cost of production.

2.7 As regards to imposition of duty they have requested that the duty may be recommended in terms of US \$ only as in the Preliminary Findings.

Comments of petitioners :

2.8 on submissions of the Dyestuff Manufacturer Association of India:

The Petitioners have pointed out that the issue of dumping is not open to an importer. This issue can, at best, be raised by an exporter only. In fact, CEGAT has prevented an importer even from arguing on the issue of dumping margin. So far as the exporters are concerned, no objection has been raised by the exporters in this regard, which itself shows that there is dumping.

As regards to calculation Of Landed Value, petitioners have pointed out that while calculating landed value, the association has considered SAD 4% and port expenses for calculation of landed value, whereas for calculation of landed value, preliminary findings states as under:

*“ Landed value for imports for the purpose shall be the assessable values as determined by the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under section 3, 3A, 8B, and 9A of the Customs Tariff Act.”*

SAD, which has been added by the association for calculation of landed value, can not be included to calculate landed value, as sales tax is also not included for the purpose of determination of net sales realization. Further, CEGAT has already held that port expenses can not be added for calculation of landed value.

It has been argued that there is no dumping of Aniline from European Union. The Association has alleged present export price of US \$ 650 pmt. It is clarified that the post investigation export price is not at all relevant to determination of the dumping in the investigation period.

*The association has stated that the Indian industry has increased its selling prices recently.*

*It may be seen from the information already filed that the domestic industry was forced to sell the material at prices significantly below cost of production. It can not be expected from the industry that it would continue to sell the material at prices significantly below the cost of production, as the same would leave the industry unviable and sick in the long run, as would be seen from the following table:*

Year	Loss
1996-97	100
1997-98	127
1998-99	221
Investigation period	620

*Index based on 1996-97 figures taken as 100*

*The petitioners have submitted that the purpose of the anti-dumping duty is to remove the unfair advantage gained by the dumping practices and re-establish open and fair competition, as noted by the Designated Authority in the preliminary findings:*

*“Imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry”*

*It has been recognised by the Designated Authority that the prices of the subject goods may increase as a result of the proposed measure (and in fact, this is the one of the most important reasons for seeking anti-dumping duty, as the domestic industry was prevented from recovering its fair selling price). It is also relevant to point out that the cost of basic input has significantly increased after the investigation period.*

As regards to initiation of anti dumping investigations, the opposing interested parties have mentioned that the investigation has been initiated on the basis of information contained in a trade magazine, which is not correct.

Petitioners have submitted that for the purpose of the initiation, the Designated Authority requires *prima facie* evidence of dumping. In the petition, the domestic industry has established dumping on the basis of information provided by a trade magazine, which was sufficient to establish *prima facie* dumping. Upon initiation, the Designated Authority has provided due opportunity to the exporters from European Union to respond and provide the information in the form and manner prescribed by the Designated Authority. No exporter from European Union has responded to the Designated Authority. Such being the case, the issue of dumping margin can not now be raised by importers or their Association.

They have reiterated that the issue of determination of normal value and dumping margin can not be argued by an importer or user Association, as they are not privy to the relevant information.

As regards to arguments with regard to domestic industry's inability to meet the demand, Petitioners have submitted that the statement of the association is factually incorrect as is evident from the table below. The demand of Aniline in India and capacities with the Indian industry were as under:

Particulars	1997-98	1998-99	POI	In MT 1999-00*
Imports from Subject Countries	251	172	2652	3536
Imports from Japan/USA	5298	5065	0	0
Imports from other Countries	259	41	43	57
Sales of domestic industry	38373	35820	31468	41957
Demand	44181	41098	34163	45550
Installed Capacity	48500	54100	40575	54100

\* Annualized

It is evident from the above that the industry has sufficient capacity to meet the demand. Such being the case, it is not understood how the

interested parties have argued that the domestic industry is not able to meet the demand of Aniline in India.

They have submitted that the industry is not required to be able to meet the demand of the product in the country before seeking the relief. The Designated Authority has notified anti-dumping duties on a number of the product wherein the demand of the product have been far higher than the capacities available in the country. Moreover, Imposition of anti-dumping duty does not restrict imports in any way. Such being the case, the users would be free to source their material as per their choice.

As regard to argument that the theory of price undercutting is false and untrue. Petitioners have submitted that the argument is factually incorrect and deserves to be ignored. The data submitted clearly show that there is significant price undercutting in the investigation period.

As regards to association argument that there were no imports of Aniline in Aug-Dec 99 and, therefore, there was no injury in that period, Petitioners have submitted that injury to the domestic industry has to be seen in whole of the investigation period and not in a month or a day. They have stated that the imports as well as other injury parameters are required to be seen in the investigation period as a whole. Ill effect of a large import consignment on the domestic industry is felt on a much longer period.

The association has stated that the petitioners' allegation of dumping is against Germany only and, therefore, duty should be imposed against Germany only and not against European Union.

There are many producers of Aniline in the European Union. There is no custom boundary in European Union and the prices prevailing in the European Union are in the same region. The imposition of anti-dumping duty will not be effective without imposing duty against imports of Aniline from the European Union as a whole as other producers may start dumping Aniline (after imposition of anti-dumping duty) at prices at which it was exported in the investigation period, resulting in continued dumping in the Indian market. Even circumventing Anti-dumping duty by the exporters/producers would not be difficult. The Designated Authority is requested to impose anti-dumping duty against imports from the European Union, as has been done in many other cases.

Further, as also stated in the preliminary findings, producers who have responded to the Designated Authority have stated in their response stated that these producers have not exported Aniline to India in the investigation period. Evidently, there are other exporters in European Union who has exported Aniline to India. Thus, imposition of anti-dumping duty cannot be effective without imposing duty against European Union as a whole. Petitioners have requested the Designated Authority to confirm anti-dumping duty against European Union as a whole.

It has been stated by the association that the imposition of anti-dumping duty on imports of Aniline will lead to increase in their cost of production, which may lead to increase in the imports of dyestuff from China.

Petitioners have submitted that the theory and practice of the Designated Authority is to save both interested parties. In case, there is any threat of injury to the downstream industry, they are free to approach the Designated Authority or any other appropriate authority and not in creating hurdles for the Aniline industry to get adequate protection of anti-dumping duty against dumping resorted by the producers and other exporters from European Union.

#### 2.9 On representation by GDMA

As regards to inadequate capacity of domestic industry to fill the gap between demand and supply, the petitioners have already represented that due to lack of demand, the domestic industry has been forced to operate their plant at reduced capacity and have carried substantial inventories during the period of investigation. They have reiterated that inability of domestic industry to meet the demand is no reason for not imposing anti-dumping duties as the imposition of anti dumping duty would merely bring prices to a fair level and would not restrict the imports into the country. Hence, the availability of product cannot suffer on this count.

As regards the arguments raised by GDMA that import of Aniline is inevitable due to export of various products, petitioners have reiterated that anti-dumping duty is not payable against imports for export production.

As regards to indication of present export price of Aniline at US \$ 650 per MT it is reiterated that present export price is not relevant to decide the issue of dumping causing injury to the domestic industry in the investigation period.

As regards to argument that prices in Europe were about US \$ 650-655 PMT during period of investigation, the export price to India during the same period were at an average of US\$ 413 PMT(CIF). Considering the ocean freight and other expenses the Ex-factory realisation to the exporters were far lower than the price of US\$ 650 PMT quoted by GDMA. This proves dumping.

The petitioners have also pointed out CEGAT rulings in a number of cases that the issue of dumping and dumping margin is not open for an importer to argue. The importer (user association) is no privy to the actual information required for assessment dumping and dumping margin. Hence the argument is required to be rejected on this count.

The petitioners have stated that the user industry's claim that Dupont's submission of US \$ 150 PMT as the conversion cost of the product, there is no basis for this claim or the importer or the user association is privy to such data.

As regards to increase in prices of Aniline after the period of investigation the same is not relevant to raise the issue of dumping or injury in the investigation.

Referring to a meeting called by GDMA and Dyestuff Manufactures Association of India at Bombay on 21.3.2001 to discuss the offer made by M/s.NCPL at the instance of Designated Authority during the public hearing to exporter, the option of supplying material to the consumer at a fair value, the users have not shown very keen interest in such a meeting. The petitioners have reiterated that the purpose of seeking anti dumping duties were merely to remove the unfair advantages of dumping gained by the exporters and short term gains taken by the consumers.

As regards to M/s BASF, the company has not exported any material during the investigation period. Without any exports, no separate assessment could be done by the Authority. The companies, who have not exported any material in an investigation period are required to file an application for "New Shipper Review" before the Designated Authority.

Further, with regard to determination of normal value in European Union on the basis of response filed by the BASF, petitioners have submitted that the BASF has not exported any material in the investigation period to India. The exporter, who has exported in the investigation period, has not responded to the Designated Authority. Determination of normal value for non-cooperative exporters on the basis of response filed by the exporter will lead to a reward by the Designated Authority for their non-cooperation. Petitioners have submitted that the normal value for non cooperative exporters should not be determined on the basis of response filed by the exporter who has not exported any material to India in the investigation period and is entitled for a "New Shipper Review" under rule 22 of Indian Anti-Dumping Rules.

### C VIEW OF THE EXPORTERS & IMPORTERS

#### Views Of The Exporters

##### 2.10 M/s. BASF, Germany :

The producers of Aniline in Germany have stated that they have not exported Aniline during the period of investigation. However, they have furnished some information on sales in home market. M/s BASF has requested that the normal value be based on their information furnished.

### VIEWs OF IMPORTERS

#### 2.11 M/s. National Organic Chemical Industries Ltd.(NOCIL)

They have stated that M/s. BASF during the Public Hearing, asserted that the normal value indicated by the petitioners may be prices charged for small volume drum lots and the regular prices should be lower for large bulk shipments.

M/s.BASF offered to submit information on normal value despite not having exported any production during POI.

They have stated that the contentions of the petitioners that the prices have been increased by marginal amount of Rs.1500 per ton after imposition of anti-dumping duties against EU in November does not hold water since price hikes have been regular and sustained in the past periods.

Injury to domestic industry has not been established in terms of volume, price realisation and profitability. Further causal link between dumping and injury has not been established.

As regards to price undertaking between producers and consumers of Aniline, M/s. NCPL preferred cost plus price arrangement and both interested parties may be given adequate time to discuss and arrive at mutually acceptable arrangement.

As regards to import statistics they have submitted that petitioners cannot claim confidentiality with regard to information collected by them from Kandla Port.

They have stated that assuming that the two manufacturers of Aniline in Germany referred to by the petitioners have been exporting Aniline to India does not establish that the same has caused or threatened to cause material injury to the petitioners.

#### 2.12 M/s. Color Chem Limited (Clariant), Thane

The importers have stated that levy of anti-dumping duty has badly affected rubber chemicals, pigment and dyestuff manufacturing units.

Small scale producers who prefer to purchase raw material packed in barrels from indigenous manufacturers vis-à-vis imported Aniline if imported in barrels caused additional imports unviable.

The anti dumping duty on Aniline is harming very interest of the down stream units due to high cost of inputs.

#### 2.13 The Dyestuff Manufactures Association of India, Mumbai:

They have stated that there is no dumping of Aniline by manufacturers/traders of European Union. The international price of suppliers from EU does not hurt the domestic manufacturers because the landed cost of Aniline imported is higher than price charged by the domestic industry.

They have stated that the domestic manufactures have continuously increased their prices of Aniline, which has affected the cost of various down stream products of Aniline consumers.

The price information based on Trade Magazine is not reliable and cannot be treated as a confidential information.

The aggregate capacity of domestic manufacturer is less than the demand in the country. Hence, there is bound to be imports of Aniline into the country.

Since the allegation of dumping are only in respect of two manufacturers in Germany the petitioners who seek imposition of duty of Aniline originating from Germany only and not anywhere from European union.

The importers have stated that coincidentally local prices of three products on which anti-dumping has been imposed namely, Aniline, Sodium Nitrite and Caustic Soda have increased substantially. The domestic industry has been increasing their prices at the cost of consuming industries.

**2.14 M/s. Gujarat Dyestuff Mfrs. Association (GDMA), Ahmedabad:**

M/s. GDMA had requested that grant of hearing to submit their case in the present anti-dumping investigations. The meeting was held on 20.3.2001. They have stated that they had submitted their objections and suggestions based on Gazette Notification dated 21.11.2000. However, they did not receive copies of rejoinders submitted by the domestic manufacturers in this regard. The import of Aniline is inevitable to bridge demand and supply gap.

M/s. GDMA has also raised issues similar to other importers.

**2.15 M/s. Mardia Chemicals Ltd, Ahmedabad.**

They have stated that prices of Aniline have been increased in the domestic market during August 2000 to April 2001 by the petitioners.

**2.16 M/s. Ganesh Chemicals, Mumbai**

They have stated that the domestic manufacturers of Aniline were not able to produce and supply the product Aniline due to their domestic and other problems faced by them. The international prices of Aniline

have been low as raw material prices have also come down during the period.

3.0 Examination by the Authority:

3.1 As regards to imposition of anti-dumping duty against Japan and USA would naturally culminate in improvement of domestic prices of Aniline.

3.2 As regards to imports volumes shifted from Japan/USA to Europe it is clarified that the volumes from Japan/USA are nil during POI compared to increased volumes from European Union.

3.3 As regards to copy of non-confidential version of response from other interested parties the same has been placed in the Public File for inspection by any interested party.

3.4 As regards to representation from GDMA it is clarified that they had not responded to the investigations before the Preliminary Findings nor they attended the public hearing on 13.2.2001. However, on representation for request for grant of hearing, Authority permitted them to put their views and the same has been considered in the final findings.

3.5 As regards to some interested parties arguments that the annulisation of various data is wrong, it is clarified that the investigation period in the present investigation is nine months. In order to compare the imports in the investigation period with previous period, it could be in terms of monthly data or in terms of yearly data. For the purpose of uniformity the previous years data has been compared with annualized data for the period of investigation. Further, In so far as the issue of ratio is concerned, it need be appreciated that the ratio remains

unchanged whether the annualized data is taken or the absolute data is taken.

- 3.6 The association have argued that imposition of Anti Dumping Duty on imports of Aniline will adversely affect the down stream products industry, as it will lead to increase in the prices of Aniline in the Indian market, which will result in increase in cost of production of dye stuff industry.
- 3.7 While it is not disputed that the imposition of Anti Dumping Duty will result in increase in prices of Aniline in the Indian market, it is clarified that the issue of public interest as explained in para K on 'Indian Industries Interest and Other Issues" of the findings.
- 3.8 As regards to M/s BASF, the company has not exported any material during the investigation period. Without any exports, no separate assessment could be done by the Authority. The companies, who have not exported any material in an investigation period are required to file an application for "New Shipper Review" before the Designated Authority.
- 3.9 As regards to M/s BASF furnishing information on normal value, Authority notes that when the company has not exported the good under consideration the assessment of normal value cannot be done and the information furnished is not relevant for assessing the normal value for other exporters who have not cooperated with the anti dumping investigation. In the circumstances the information furnished by M/s BASF has not been considered.

The Indian Anti-Dumping Rules states as under in this regard :

Margin of dumping for exporters not originally investigated

(1) *If a product is subject to anti dumping duties, the Designated Authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.*

3.10 As per rules the determination of dumping margins are exporter specific. As M/s BASF have not exported product under consideration during the period of investigation, there is no question of determining dumping margin for them separately based on the information furnished by the company.

3.11 In the above circumstances, Authority notes that the company is required to file an application for "New Shipper Review" after completion of the present investigation.

**D EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED**

4. The foregoing submissions made by the petitioner, exporters, importers and other interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and to the extent these have a bearing upon the case, have been examined and considered and have been dealt with at appropriate places in these findings.

**E PRODUCT UNDER INVESTIGATION**

5. The product under consideration in the present investigation is aniline also known as Aniline oil. Aniline is a transparent, oily, Colourless to

pale yellow liquid when freshly distilled. It darkens on exposure to light or air. Aniline is a primary amine compound and a basic organic chemical essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline is also used in some other industries such as rubber chemicals, explosives, resins etc.

Aniline is an intermediate for Rubber Chemicals (vulcanization, accelerators, antioxidants), Dyes, Drugs such as analgin, Sulpha drugs, Photographic chemicals (hydroquinone), Isocyanates (MDI or Methylene Diphenylene Di-Isocyanate). In India, 70% of the production of Aniline is used in rubber chemicals, drugs and drug intermediates and dye industries, whereas 80% of production of Aniline world-over is used in MDI.

Aniline is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under custom sub-heading no. 2921.41. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

## F      LIKE ARTICLE

### 6.1    Definition of Like Article states as under:

“Like Article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”

### 6.2    Aniline is product and sold in specifications as per ISI standards, which depict the properties of the chemical. The quality of Aniline is described in terms of its purity. The standard quality of Aniline normally contains 99.8% purity by weight. There is however, no significant difference in terms of process, equipment or technology for the production of aniline.

6.3 The Authority finds that Aniline produced by the petitioners and the subject product imported from European Union are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, function and uses, products specifications etc. The two are technically and commercially substitutable.

6.4 In light of the foregoing, Authority concludes that Aniline produced by the petitioner is a Like Article to the Aniline imported from European Union.

#### G DOMESTIC INDUSTRY

7.0 M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL), M/s. Narmada Chematur Petro Chemicals Ltd. (NCPL), and M/s. Anirox Pigments Ltd., have jointly filed the petition. These three units are the only producers of Aniline in India. The petitioner companies, therefore, account for total domestic production and have the required standing to file the petition under the Rules.

7.1 In light of the foregoing, the Authority concludes that the petitioner has the standing to file the petition on behalf of the domestic industry under the rules.

#### H DUMPING:

8.0 Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article, means-

- (i) "the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin alongwith reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin".

Claims of the Exporters:

- 8.1 M/s BASF : They have stated that they have not exported Aniline during the Period of Investigation. They have also requested that the normal value be based on their information furnished in their home market and have indicated that they intend to export Aniline to India in near future.
- 8.2 M/s Bayer: They have stated that within the investigation period 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> December, Bayer AG has not exported Aniline to India.

**EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

- 8.3 Authority notes that the Two exporters, viz. M/s BASF, Germany and M/s Bayers AG, Germany have stated that they have not exported Aniline during the POI and may request for separate assessment as a new shipper - Rule 22 supra.
- 8.4 As regards to M/s BASF furnishing information on normal value, and some interested parties claim that the determination of normal value for Germany to be based on the same, Authority notes that the information provided by the company is not sufficient to determine normal value. The company has furnished factory cost and profit of domestic sales for the period of investigation and exports to countries other than India, they have not furnished any details /working calculations linking to their audit and accounts which would demonstrate that the product was sold above cost of production. It

also does not establish that they have sold the subject goods in their home market or to the countries other than India in ordinary course of trade. The Annual Report for 1999 seems to be consolidated one. Very little is reported about the product under consideration. The company has furnished some selective invoices with respect to their home sale in German language without corresponding English version. Authority further notes that when the company has not exported the good under consideration the assessment of normal value cannot be done and the information furnished is not relevant for assessing the normal value for other exporters who have not cooperated with the anti dumping investigation. In the circumstances the information furnished by M/s BASF with regard to normal value has not been considered.

8.5 In view of the non-submission of information to the questionnaire by any other producers/ exporters from EU, the Authority have been constrained to rely upon best available information with regard to normal value and export price as provided by the petitioners and the best information available with it.

**Normal Value**

8.6 The petitioners have provided evidence relevant to POI with respect to prices in Europe based on a Magazine Chemical Week UK which reported CIF prices of Aniline in European markets in the region of US \$ 880 – 925 PMT. The Authority relies upon the claim made by the petitioner with regard to normal value as at ex-factory in European Union and as the best information on record. The normal value is determined at US \$ \*\*\* PMT.

**Export Price**

8.7 The petitioners have provided the export data as reported by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S, Calcutta) for the period April-December, 1999. The volume of imports from EU is reported at 1251.7 MT and have claimed adjustments on

account of Ocean freight, commission, inland transportation, port handling to arrive at ex-factory export price.

8.8 The import data as reported by Customs daily list, Kandla Port indicates the volume of 2652 MT from European Union during the POI, which is much higher than that reported by DGCI&S. The Authority has relied on the import data for POI as reported by Customs. The Authority has allowed adjustments on account of Ocean freight, commission, inland transportation, port handling charges and export price (ex-factory level) has been accordingly determined, at US \$ \*\*\* PMT.

#### Dumping Margin

8.9 The Rules relating to comparison provides comparison of normal value and export price provides as follows:

"While arriving at margin of dumping Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. A comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level and in respect of sales made and as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case on its merits, for differences which occur price comparability including differences in conditions and terms and sales, taxation, levels of trade quantities, physical characteristics and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

8.10 For the purpose of fair comparison between normal value and export price the Authority took into account the information furnished by the petitioner and other published information available with the Authority. The normal value and export prices determined as detailed above are at ex-works level. The comparison of normal value and export price works out to a dumping margin of \*\*\*PMT. The dumping margin expressed as a percentage of export price for EU works out to 166.17%.

## I INJURY

9.0 Under Rule 11 supra, Annexure-II, When a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree;

Rule (iii) of the Annexure II to the Rules requires that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, The Authority will cumulatively assess the effect of such imports. Such assessment can be, however, made only if it is determined that:

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of the like article or where the export of individual countries less than three percent, the imports collectively accounts for more than seven percent of the import of Like Article and
- b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

9.1 The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject country are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject country were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market.

9.2 For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry such as quantum of Imports

production, capacity utilisation, sales quantum, stock, market share, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

### 9.3 Quantum of Imports :

The Volume of imports as reported by DGCI & S have been as under :

	1997-98	1998-99	POI Apr-Dec.99)	((Annualised)
Import from EU(MT)	251	172	*2652	(3536)
Share of EU in total import(%)	4.3	3.3	98.4	
Imports from Japan / USA	5298	5065	0	(0)
From other countries(MT)	298	40	43	(57)
<b>Total Imports (MT)</b>	<b>5847</b>	<b>5277</b>	<b>2695</b>	
Sales of Indian Producers(MT)	38373	35820	31468	(41957)
<b>Total Demand in Country (MT)</b>	<b>44220</b>	<b>41097</b>	<b>34163</b>	<b>(45550)</b>
<u>Market Share in Demand</u>				
EU	0.6	0.5	7.8	
Japan/USA	11.9	12.3	0	
Others	0.7	0.1	0.1	
Domestic Industry	86.8	87.1	92.1	
	100.0	100.0	100.0	

\* Source Customs Daily List- Kandla Port.

As may be seen from the above, the volume of imports from EU which was 251 MTs during 1997-98 increased to 2652 MT (3536 MT Ann.) in 1999-2000. The share of European Union in total imports raised from 4.3% in 1997-98 to 98.4% in POI. The volume of imports from Japan,USA which was 5298 MT (97-98) reduced to Nil during POI. It is noted that the anti-dumping investigations for alleged dumping from Japan/USA were in progress before the initiation of the present investigation against EU.

While the market share in demand with respect to European Union have increased manifold from 0.6% (97-98) to 7.8% (POI). Market share with respect to domestic industry has also shown increase from 86.8% (97-98) to 92.1% (POI).

As seen the market share in demand for Japan/USA in previous years has been shared by major proportion by EU and to a small extent by a domestic industry during the POI.

#### 9.4 Production and Capacity Utilisation

It is observed that the production capacity, production and capacity utilization of the petitioner companies (viz., HOCL, NCPL and Anirox Pigments) were as under:

Year	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation %
1996-97	48100	40435	84.06
1997-98	48500	47254	97.43
1998-99	49100	41780	85.09
POI(Apr-Dec)	36825	32768	88.98
Annualised	49100	43689	88.98

The production of domestic industry decreased from 47254 MT in 1997-98 to 43689 MT (Ann.) during the period of investigation. The capacity utilization which was 97.43% during 1997-98 decreased to 88.98 during POI.

#### 9.5 Sales Volume:

The sales volumes of domestic industry in the last three years were as under :-

In MT			
1997-98	1998-99	POI	Annualised
38373	35820	31468	41957

The domestic industry has lost substantial sales in 1998-99. Though the sales have improved in the current year, the same is at the cost of substantial losses made by the individual units in respect of Aniline operations.

9.6 **Closing Stock:**

In MT

1997-98	1998-99	POI	Annualised
2226	2252	2881	3841

It may be observed that the closing stock of petitioners were 2226 MT during 1997-98 have increased to 2881 MT during POI.(April-Dec.99)

9.7 **Price undercutting**:- The landed price of imports from EU is significantly lower than the selling price of domestic industry. As such the domestic industry is selling at prices significantly below their cost of production. The imports from EU are thus causing severe price undercutting of the domestic industry.

9.8 **Domestic Sales:**

( in %)

	1997-98	1998-99	POI(Apr to Dec /99)
HOCL	100	93	88
NCPL	100	89	81
Anirox	100	98	87
Average for Domestic Industry	100	91	85

As seen from the above the domestic sales prices in terms of % have declined during POI compared to 1997-98. The Authority notes that imports were undercutting the prices of Indian industry to a significant degree. This has prevented the industry from increasing their selling prices.

9.9 **Conclusions of Injury:**

- The volumes of imports from EU have increased sharply during POI.
- The CIF import price has been declining.

- The production of capacity utilization has shown decline during POI compared to year 1997-98.
- The market share of imported goods from EU has gone up.
- The cost of production in the domestic industry has gone up during the POI but the realisations have gone down during POI. Thus the domestic industry has suffered losses during the POI.
- Imports from subject countries resulted in price undercutting in Indian market.

9.10 The Authority, after considering the above, concludes the domestic industry has suffered material injury from imports of Aniline originating from EU.

J **CAUSAL LINK**

10.0 The Authority notes that there have been no major fluctuations in demand for Aniline in India. The domestic industry is one of the smallest producers of Aniline in the world and the capacity of Indian industry is adequate to meet the demand for Aniline in India. The global prices of Aniline dropped significantly in 1998-99 and had an impact on the prices at which it was imported to India. This affected the operations and profitability of the domestic producers as aniline was dumped by major international manufacturers. During the period of investigation.

10.1 In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from the subject countries, the Authority holds that the increase in market share of imports from European Union resulted in reduced market share of the petitioners. The domestic industry failed to match the landed price of the imported product on account of the rise in prices of the inputs/feedstock required for the manufacture of aniline. Prices of petroleum, fuel oil and benzene started firming up from 1996 onwards. Imports from the subject countries undercut the prices of the

domestic product forcing the domestic industry to sell at un-remunerative prices. Resultantly, the domestic industry incurred losses. The material injury to the domestic industry was, therefore, caused by the dumped imports from the subject country.

#### **K INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

- 11.0 The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- 11.1 It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of aniline. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 11.2 To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority relied upon reasonable selling price of Aniline in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilization for the domestic industry.

## L CONCLUSIONS

12.0 It is seen, after considering the foregoing, that:

- Aniline originating in or exported from European Union has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- The Indian industry has suffered material injury;
- Injury has been caused by imports from the subject country;

It is considered necessary to impose anti-dumping duty, on all imports of Aniline originating in or exported from the subject country.

13.0 Authority considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry, and the date of commencement of such duty (clause (d) Rule 4 supra as amended).

14.0 It was decided to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duty be imposed, on Aniline originating in or exported from European Union falling under Customs sub-heading 2921.41 of the Customs Tariff Act,. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Col.3.

Country	Name of the Producer/Exporter	Amount of Duty US \$ per Kg
1	2	3
European Union	All exporters	0.342

15.0 Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B and 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

16.0 Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 14.08.2000 and corrigendum dated 6.11.2000.

17.0 An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority